के अन्त में मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, निम्न प्रकार थी :

(हजार में)

वर्ष	कुल	महिलाएं	शिक्षित (मैट्रिक व उस से ऊपर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1989	1978.6	289.5	1248.0	241.8	155.0
1990	2067.2	317.0	1412.6	251.7	172.1
1991	1990.9	284.6	1393.0	252.4	164.0

जिला-वार सूचना का अनुरक्षण नहीं किया जाता। आदिवासियों के संबंध में पृथक सूचना का अनुरक्षण भी नहीं किया जाता।

1989 तथा 1990 के दौरान (नवीनतम उपलब्ध) मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सरकारी तथा अर्ध-सरकारी नौकरियों में प्रभावित नियुक्तियां निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	नियुक्तियां (हजार में)	
	सरकारी	अर्ध-सरकारी
1989	22.8	4.5
1990	16.0	4.8

सरकारी तथा अर्ध-सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाए गए व्यक्तियों की संख्या का पृथक अनुरक्षण नहीं किया जाता।

निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, सम्प्रेषण हेतु चयन का आधार नियोजक द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत आवेदक की गुणात्मकता तथा उपयुक्तता है।

बिहार में प्रति व्यक्ति आय

5351. श्री एस. एस. अहलुवालिया : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने बिहार में प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है,

(ब) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए बिहार राज्य के लिए सतत (1980-81) कीमतों पर तथा अखिल भारत निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार है :

(रुपए)

	1990–91	1991–92 (अनन्तिम)	1992–93 (तुरंत अनुमान)
बिहार	1195	1098	1091
अखिल भारत	2213	2167	2216

बिहार में कम प्रति व्यक्ति आय के कारणों का पता लगाने के लिए योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। बिहार सरकार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधार-संरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास के लिए निवेश तथा गरीबों को सीधे रोजगार तथा आय पैदा करने के लिए कुछ कार्यक्रम शामिल हैं। केन्द्र सरकार भी केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को सहयोग देती है।

National Income spent on Urban Development Schemes

5352. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the total urban population in the country as per the latest census;

(b) the percentage of national income being spent presently on urban development schemes; and

(c) the steps taken to increase the expenditure on urban development schemes keeping in view the urban population?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) (a) As per the 1991 census the total urban population of India is estimated at 217 million.

(b) In 1992-93 the outlay for Urban Development schemes was Rs. 970 crores (State Sector Rs. 855 crores and Central Sector Rs. 115 crores). The estimated National income for the same year was Rs. 622588 crores. Calculations of percentage is not meaningful as National income comprises of both consumption and investment expenditures, both Public and Private.

(c) During the Seventh Five Year Plan, an outlay of Rs. 1,801 crores (Rs. 1,633 crores in the State Sector and Rs. 168